शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
Directorate of Education, GNCT of Delhi
Suggestive Answer of Practice Paper 2
अभ्यास प्रश्न-पत्र **2** के सुझावात्मक उत्तर

कक्षा **– XII**

CLASS – XII

अर्थशास्त्र **(030)**

Economics (030)

सत्र **– II (2021-22)**

TERM II (2021 – 22)

अधिकतम अकं **: 40** | समय**: 2** घंटे

Max Marks: 40 | **Time: 2 hrs**

Q N. प्र. सं.	Expected Answer अपेक्षित उत्तर	**Marks** अंक
1	Given : Nominal GDP is Rs 500 crore and Price Index 150. Real GDP = (Nominal GDP/ Price Index) × 100 = (500 / 150) × 100 = ₹ 333.33 crore **OR** Yes, The given statement is correct. In a two sector economy households render factor services to the firms and earn factor incomes from them. Whereas; firms produce and sell goods and services to households and earn their income. The factor income earned by the households will be used to buy the goods and services which would be equal to the income of firms. The aggregate consumption expenditure by the households in the economy is equal to the aggregate expenditure on goods and services produced by the firms in the economy (Income of the producers). **(Marked as a whole)** दिया गया है: मौद्रिक जीडीपी 500 करोड़ रुपये और मूल्य सूचकांक 150 है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद = (मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद / मूल्य सूचकांक) × 100 = (500/150) × 100 = ₹ 333.33 करोड़ अथवा हाँ, दिया गया कथन सही है। द्वि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार फर्मों को कारक सेवाएं प्रदान करते हैं और उनसे कारक आय अर्जित करते हैं। जबकि; फर्में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं और गृहस्थों को बिक्री कर अपनी आय अर्जित करती हैं। परिवारों द्वारा अर्जित कारक आय का उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाएगा जो फर्मों की आय के बराबर होंगी। अर्थव्यवस्था में परिवारों द्वारा कुल उपभोग व्यय अर्थव्यवस्था में फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय (उत्पादकों की आय) के बराबर है। **(एक साथ मूल्यांकित किया जाय)**	**2** **2** **2** **2**

2	The steps taken by the Central Bank to boost the falling demand in the economy are justified as the reduction in the Repo rate and Reverse Repo Rate will increase the availability of loans in the market through the commercial banks. A decrease in Repo/Reverse Repo Rate will eventually make the borrowings cheaper for the general public. As a result the consumption demand in the economy may increase. **(Marked as a whole)** **OR** K = 1 / 1 - MPC = 1 / 1 - 0.8 = 5 K = ΔY / Δ I 5 = 2000 / Δ I Δ I = 400 Increase in investment= 400 crores अर्थव्यवस्था में गिरती मांग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए कदम उचित हैं क्योंकि रेपो दर और विपरीत रेपो दर में कमी से वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से बाजार में ऋण की उपलब्धता में वृद्धि होगी। रेपो/रिवर्स रेपो दर में कमी आम जनता के लिए ऋण लेना सस्ता कर देगी। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में उपभोग मांग बढ़ सकती है। **(**एक साथ मूल्यांकित किया जाय**)** अथवा गुणक K = 1/1 - MPC = 1 / 1 - 0.8 = 5 K = Y / ΔI 5 = 2000 / ΔI ΔI = 400 करोड़ निवेश में वृद्धि = 400	**2** **2** **2** **2**
3	We know that MPC+MPS= 1 If MPS is increasing, MPC will decrease, leading to a fall in consumption as a very important component of aggregate demand, leading to a fall in the equilibrium level of income leading to slow down or recession. **(Marked as a whole)** हम जानते हैं कि MPC + MPS = 1 यदि MPS बढ़ रहा है, तो मापक घटेगा, जिससे समग्र मांग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में उपभोग में कमी होगी, जिससे समग्र मांग में कमी होगी। परिणामस्वरूप आय के संतुलन स्तर में गिरावट आने से मंदी आ जाएगी। **(**एक साथ मूल्यांकित किया जाय**)**	**2** **2**
4	In 1972 - 73, about 74 % of the workforce was engaged in the Primary sector and in 2017 - 18,this proportion has declined to about 40%. Secondary and service sectors are showing promising futures for the Indian workforce as shares of these sectors have increased from 11 to 24% and 15 to 31 percent respectively during 1972 - 2018. **(Marked as a whole)** 1972-73 में, लगभग 74% कार्यबल प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ था और 2017-18 में, यह अनुपात घटकर लगभग 40% हो गया है। द्वितीयक और सेवा क्षेत्र भारतीय कार्यबल के लिए आशाजनक भविष्य दिखा रहे हैं क्योंकि 1972 - 2018 के दौरान इन क्षेत्रों के शेयरों में क्रमशः 11 से 24% और 15 से 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। **(**एक साथ मूल्यांकित किया जाय**)**	**2** **2**

5	It is rightly said that health care in India suffers from urban-rural and rich-poor divide. 70% of the population is living in rural areas while only 20% of the hospitals are located in rural areas. It means 80% of hospitals are serving 30% of the population. There are only 0.36% hospitals for one lakh people in rural areas whereas there are 3.6% hospitals per one lakh population in urban areas, i.e. number of hospitals in urban areas is 10 times the number of hospitals in rural areas. In villages, specialised medical care is completely missing like pediatrics, gynecology, anesthesia and obstetrics. PHCs located in rural areas do not even have X-ray or blood test facilities. 20% of doctors passing leave the country for better prospects. Many others are interested in urban areas, rare are the ones interested in rural areas. The poorest one fifth spends 12% of their income on health while the rich spend only 2% of their income on health. **(Marked as a whole)** **OR** Worker population ratio is an indicator which is used to analyse the employment situation in the country. It is measured as a ratio of workforce to total population of the country. Worker Population ratio = (Total Number of Workers / Total population) × 100. यह सही कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल शहरी-ग्रामीण और अमीर-गरीब विभाजन से ग्रस्त है। 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है जबकि केवल 20% अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इसका अर्थ है कि 80% अस्पताल 30% जनसंख्या की सेवा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख लोगों के लिए केवल 0.36% अस्पताल हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रति एक लाख आबादी पर 3.6% अस्पताल हैं, यानी शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या से 10 गुना है। गांवों में, विशेष चिकित्सा जैसे बाल रोग, स्त्री रोग, संज्ञाहरण और प्रसूति देखभाल पूरी तरह से गायब है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पीएचसी में एक्स-रे या रक्त परीक्षण की सुविधा भी नहीं है। पास होने वाले 20% डॉक्टर बेहतर संभावनाओं के लिए देश छोड़ देते हैं। कई अन्य शहरी क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि रखने वाले दुर्लभ हैं। सबसे गरीब पांचवां हिस्सा अपनी आय का 12% स्वास्थ्य पर खर्च करता है जबकि अमीर अपनी आय का केवल 2% स्वास्थ्य पर खर्च करता है। **(**एक साथ मूल्यांकित किया जाय**)** अथवा श्रमिक जनसंख्या अनुपात एक संकेतक है जिसका उपयोग देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसे देश की कुल जनसंख्या में कार्यबल के अनुपात के रूप में मापा जाता है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात = (श्रमिको की कुल संख्या / कुल जनसंख्या) × 100	**2** **2** **2** **2**
6	Given , Consumption function(C) = 200+0.5Y, Investment(I) = 400, Level of income (Y)=1500 At Equilibrium level AD = AS, Y = C+I thus, Y = (200 + 0.5Y) + 400 Y – 0.5 Y = 600 Y = 600/0.5 = ₹ 1200 crores. The equilibrium level of income = ₹ 1200 crores. The given income (₹ 1500 crores) is greater than equilibrium level of income (₹ 1200 crores). Therefore, the economy is not in equilibrium. **OR** This is the situation of Deficient Demand. Following two fiscal measures may be taken to control it:	**1** **1** **1** **1.5**

	a. Decrease in Taxes Rates - To curb the situation, the government may decrease the taxes. This may increase the purchasing power in the hands of the general public. This may increase the Aggregate Demand in the economy. b. Increase in Government Expenditure - The government may also increase its expenditure. This increases the flow of money in the economy which in turn may increase the Aggregate Demand in the economy. दिया गया है, उपभोग फलन (C)=200+0.5Y, निवेश(I)=400, आय का स्तर (Y)=1500 संतुलन स्तर पर AD = AS , Y = C+I इस प्रकार, Y = (200 + 0.5Y) + 400 Y - 0.5 वाई = 600 Y = 600/0.5 = ₹ 1200 करोड़। आय का संतुलन स्तर = ₹ 1200 करोड़। दी गई आय (₹ 1500 करोड़) आय के संतुलन स्तर (₹ 1200 करोड़) से अधिक है। इसलिए, अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं है। अथवा स्थिति बताती है कि समग्र मांग, समग्र आपूर्ति से कम है। इसे नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित दो राजकोषीय उपाय किए जा सकते हैं: अ. करों की दरों में कमी - स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार करों में कमी कर सकती है। इससे आम जनता के हाथ में क्रय शक्ति बढ़ सकती है। यह अर्थव्यवस्था में सकल मांग को समग्र आपूर्ति के बराबर लाने के लिए बढ़ा सकता है। ब. सार्वजनिक व्यय में वृद्धि - सरकार अपने खर्च में भी वृद्धि कर सकती है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करेगा जो बदले में अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाकर समग्र आपूर्ति के बराबर कर सकती है।	**1.5** **1** **1** **1** **1.5** **1.5**
7	The health system in India has undoubtedly improved over the years but the pace of improvement has been unreasonably slow and truly we carry an unhealthy health system. Following may be the most important problems facing Indian health system: 1. Low Public Expenditure – In India the health expenditure as a percentage of GDP is very low as compared to some of the major developing countries. It stood at around 4.7% of the total GDP in the year 2014-15. 2. Urban Rural Divide – People living in rural India do not have sufficient medical infrastructure. Nearly 70% of the population lives in rural areas which have only 20% of the total hospitals of the country. 3. Women and child health issues - More than 50 percent of married women in the age group of 15–49 years have iron deficiency, which has contributed to maternal deaths. Infant Mortality Rate per 1,000 live births in India is 34. Malnutrition and inadequate supply of vaccines lead to the death of millions of children every year. भारत में स्वास्थ्य प्रणाली में पिछले कुछ वर्षों में निस्संदेह सुधार हुआ है, लेकिन सुधार की गति अनुचित रूप से धीमी रही है और वास्तव में हमारे पास एक अस्वस्थ स्वास्थ्य प्रणाली हैं। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को खराब करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चिंताएँ निम्नलिखित हैं: 1. कम सार्वजनिक व्यय - भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय कुछ प्रमुख विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। यह वर्ष 2014-15 में कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.7% था। 2. शहरी ग्रामीण विभाजन - ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के पास पर्याप्त चिकित्सा अवसंरचना नहीं है। लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिनके लिए देश के कुल अस्पतालों का केवल 20% है।	**3**

	3. महिला और बाल स्वास्थ्य के मुद्दे - 15-49 वर्ष के आयु वर्ग में 50 प्रतिशत से अधिक विवाहित महिलाओं में आयरन की कमी है, जिसके कारण मातृत्व मृत्यु होती है। भारत में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर 34 है। कुपोषण और टीकों की अपर्याप्त आपूर्ति से हर साल लाखों बच्चों की मौत होती है।	**3**
8	Reasons for the slow growth and re-emergence of poverty in Pakistan (i) Use of traditional Method in the Agricultural Sector - Pakistan government has failed to improve its agriculture through institutional reforms. Agriculture is still continue to be controlled by landlords and depend on monsoon (ii) High Dependence on Public Sector Enterprises - As public sector enterprises lack operational efficiency and poor management of scarce resources, it led to slow progress in productivity. (iii) High Dependence on Foreign Loans - In Pakistan, major foreign exchange was earned from the remittances of Pakistani workers in the Middle East and export of highly unstable agricultural products. There was a high dependence on foreign loans and this increased the problem to repay the loan amount. (iv) Lack of Political Stability - Huge public expenditure was incurred on law and order to stabilise the unfavorable political situation. This unproductive expenditure caused a drain on economic resources. (v) Inadequate Infrastructure - Pakistan was not able to attract foreign investment and trade activities because they lacked infrastructural facilities for business development. (vi) Domestic terrorism and shift in focus from economic growth to defence preparedness are also the factors for slow economic growth. **(Any three relevant reason)** पाकिस्तान में धीमी वृद्धि और गरीबी के फिर से उभरने के कारण (i) कृषि क्षेत्रक में पारंपरिक विधियों का प्रयोग - पाकिस्तान सरकार संस्थागत सुधारों के माध्यम से अपनी कृषि में सुधार करने में विफल रही है कृषि अभी भी जमींदारों द्वारा नियंत्रित है और मानसून पर निर्भर है (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर अधिक निर्भरता - चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में परिचालन दक्षता और दुर्लभ संसाधनों के खराब प्रबंधन की कमी है, इससे उत्पादकता में धीमी प्रगति हुई है। (iii) विदेशी ऋणों पर अधिक निर्भरता - पाकिस्तान में, मध्य पूर्व में पाकिस्तानी श्रमिकों के प्रेषण और अत्यधिक अस्थिर कृषि उत्पादों के निर्यात से प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी। विदेशी ऋणों पर बहुत अधिक निर्भरता थी और इससे ऋण राशि चुकाने की समस्या बढ़ गई। (iv) राजनीतिक स्थिरता का अभाव - प्रतिकूल राजनीतिक स्थिति को स्थिर करने के लिए कानून और व्यवस्था पर भारी सार्वजनिक व्यय किया गया। इस अनुत्पादक व्यय ने आर्थिक संसाधनों का अपव्यय कर दिया। (v) अपर्याप्त आधारिक संरचना - पाकिस्तान विदेशी निवेश और व्यापार गतिविधियों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं था क्योंकि उनके पास व्यापार विकास के लिए आधारिक संरचना सुविधाओं की कमी थी। (vi) घरेलू आतंकवाद और आर्थिक विकास से रक्षा तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करना भी धीमी आर्थिक वृद्धि के कारक हैं। **(**कोई तीन उपयुक्त कारण**)**	**3** **3**
9	1. Human development index 2. Life expectancy at birth 3. Mean year of schooling (% aged 15 and above) 4. Gross National income per capita 5. Percentage of people living below poverty line	

	6. Infant mortality rate 7. Maternal mortality rate 8. Population using at least basic sanitation 9. Population using at least basic water source 10. Percentage of undernourished children. **(Any six point)** 1. मानव विकास सूचकांक 2. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 3. स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष (15 वर्ष और उससे अधिक आयु का%) 4. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 5. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 6. शिशु मृत्यु दर 7. मातृत्व मृत्यु दर 8. आधारभूत स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या 9. आधारभूत पेय जल स्रोत का उपयोग करने वाली जनसंख्या 10. कुपोषित बच्चों का प्रतिशत। **(कोई छह बिंदु)**	**3** **3**
10	1.Expenditures on intermediate goods are not to be estimated otherwise it may lead to problems of double counting. We must make sure that we are not included the intermediate expenditure. 2. Expenditure on second hand goods and services is not to be included because it has already been included in the year when these goods have been manufactured, but the expenditure made on broker's Service as commission is to be included. 3. The expenditure on transfer payments is not to be included because this expenditure does not lead to production of goods and services in the economy. 4. The expenditure on illegal goods is also not to be included because these goods are not been legally sanctioned. 5. Expenditure on shares and bonds is not to be included in total expenditure as these are paper claims and are not related to production of final goods and services. Such expenditures do not cause any value addition. **(Any three)** 1.मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय को शामिल नहीं जाना चाहिए अन्यथा इससे दोहरी गणना की समस्या हो सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम मध्यवर्ती व्यय को शामिल न करें। 2. पुरानी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह पहले से ही उस वर्ष में शामिल किया गया है जब इन वस्तुओं का निर्माण किया गया था। लेकिन कमीशन के रूप में दलाल की सेवा पर किए गए व्यय को शामिल किया जाना है। 3. हस्तांतरण भुगतान पर व्यय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस व्यय से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है। 4. अवैध सामानों पर होने वाले खर्च को भी शामिल नहीं किया जाना है क्योंकि ये सामान कानूनी रूप से स्वीकृत नहीं हैं। 5. शेयरों और बांडों पर व्यय को कुल व्यय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये कागजी दावे हैं और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं हैं। इस तरह के व्यय से कोई मूल्यवर्धन नहीं होता है। **(कोई तीन)**	**1×3** **1×3**
11	The working of an investment multiplier is based on the principle that one's expenditure is another's income.	

Given initial investment = ₹ 100 crores and MPC = 0.8

Round	Change in Investment (₹ in crore)	Change in Income (₹ in crore)	Change in Consumption (₹ in crore)	Change in Savings (₹ in crore)
1	100	100	80	20
2	-	80	64	16
3	-	64	51.20	12.80
…..	-	-	-	-
…. And So on				
Total		500	400	100

(Correct explanation of table should be considered) **1**

K = 1 / 1 - MPC
= 1 / 1 - 0.8
= 5
K = ΔY /Δ I
ΔY = K × Δ I
= 5 × 100
Δ Y = 500 crore. **1**

3

निवेश गुणक का कार्य इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक का व्यय दूसरे की आय है।
दिया गया प्रारंभिक निवेश = ₹100 करोड़ और MPC = 0.8

चक्र	निवेश में परिवर्तन (₹ करोड़ में)	आय में परिवर्तन (₹ करोड़ में)	उपभोग में परिवर्तन (₹ करोड़ में)	बचत में परिवर्तन (₹ करोड़ में)
1	100	100	80	20
2	-	80	64	16
3	-	64	51.20	12.80
…..	-	-	-	-
…. और इसी तरह				
कुल		500	400	100

(तालिका की सही व्याख्या पर भी विचार किया जाना चाहिए)

K = 1 / 1 - MPC
= 1 / 1 - 0.8
= 5
K = ΔY /Δ I
ΔY = K × Δ I
= 5 × 100 **1**

3

1

	ΔY = 500 करोड़	
12	(A) (i) NNPfc = GNPmp – Depreciation – Net Indirect Taxes = 15 000 - 1000 - (500 - 150) = 14000 - 350 = ₹ 13650 crore [NIT = Indirect Taxes – Subsidies] (ii) NDPfc = GNPmp – Depreciation – Net Factor Income from Abroad – Net Indirect Taxes = 15000 - 1000 - 650 - (500 - 150) = ₹ 13000 crore (B) (i) As the profits are earned in the domestic territory of India, the profits earned by a branch of the foreign bank in India will be 'included' in the domestic income of India. (ii) Payment of salaries to its staff by the Japanese embassy located in New Delhi will 'not be included' in the domestic income of India, as it is not a part of the domestic territory of India. (iii) As interest received by an Indian resident from its investment abroad is factor income from abroad, it will 'not be included' in domestic income of India. **OR** (a) National Income (NNPfc) = Private Final Consumption Expenditure + Government Final Consumption Expenditure + Net Domestic Fixed Capital Formation + Change in Stocks − Net Imports − Net Indirect Taxes + Net Factor Income from Abroad = 750 + 250 + 220 + (-20) - 50 - 120 + 20 = 1140 - 190 = ₹ 1050 crore (b) Differentiation between Factor Income and Transfer Income. **(Any two difference)** अ) (i) NNPfc = GNPmp – मूल्यह्रास – शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = 15 000 - 1000 - (500 - 150) = 14000 - 350 = ₹ 13650 करोड़ [शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = अप्रत्यक्ष कर - आर्थिक सहायता] (ii) NDPfc = GNPmp – मूल्यह्रास – विदेशों से शुद्ध कारक आय – शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = 15000 - 1000 - 650 - (500 - 150) = ₹ 13000 करोड़	**1** **1** **1** **1** **3** **2** **1** **1** **1**

BASIS	FACTOR INCOME	TRANSFERINCOME
Meaning	Income received by factor inputs for providing productive services	Income received without providing any goods and services
Nature	Earned income	Unearned income
Estimation of N.I.	Included	Not included
Types of income	Bilateral income	Unilateral (one sided) income
Examples	Rent, wages, interest and profit	Gifts, donations, scholarships etc.

	(ब) (i) भारत में विदेशी बैंक की एक शाखा द्वारा अर्जित लाभ को भारत की घरेलू आय में 'शामिल' किया जाएगा क्योकि लाभ भारत की घरेलू सीमा में अर्जित किया गया है। (ii) नई दिल्ली में स्थित जापानी दूतावास द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भारत की घरेलू आय में 'शामिल नहीं' किया जाएगा, क्योंकि यह भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं है। (iii) चूंकि एक भारतीय निवासी द्वारा अपने विदेशी निवेश से प्राप्त ब्याज विदेशों से होने वाली साधन आय है, इसलिए इसे भारत की घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अथवा अ) राष्ट्रीय आय (NNPfc) = निजी अंतिम उपभोग व्यय + सरकारी अंतिम उपभोग व्यय + शुद्ध घरेलू अचल पूंजी निर्माण + स्टॉक में परिवर्तन - शुद्ध आयात - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर + विदेश से शुद्ध कारक आय = 750 + 250 + 220 + (-20) - 50 - 120 + 20 = 1140 - 190 = ₹ 1050 करोड़ ब) साधन आय और हस्तांतरण आय के बीच अंतर -	**1** **1** **3** **2**

आधार	साधन आय	हस्तांतरण आय
अर्थ	उत्पादक सेवाएं प्रदान करने के लिए कारक सेवाएं देने पर प्राप्त आय	कोई वस्तु या सेवाएं प्रदान किए बिना प्राप्त आय
प्रकृति	अर्जित आय	फ्री की आय
राष्ट्रीय आय का अनुमान.	शामिल	शामिल नहीं
आय का प्रकार	द्विपक्षीय आय	एकतरफा आय
उदाहरण	किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ	उपहार, दान, छात्रवृत्ति आदि।

(कोई दो अंतर)

13	(A) The present development strategy calls for maximum exploitation of natural resources. As a result nature is exploited beyond its carrying capacity. The production techniques adopted today are creating a number of environmental problems. Excess use of plastic and other non-degradable products are pausing a threat to the environment. (B) In the Past, Demand was less than Supply. In the early days of civilization, demand for environmental resources and services was much less than their supply. Pollution was within the absorptive capacity of the environment; and Rate of resource extraction was less than the rate of regeneration of these resources.As a result, environmental problems did not arise.Presently, Demand is more than supply. In the present period, the demand for resources is in far excess of supply, i.e. demand is beyond the rate of regeneration of the resources. With the population explosion and with the advent of industrial revolution, the pressure on the absorptive capacity of the environment has increased tremendously.Thus, a reversal of supply-demand relationship is responsible for degradation of quality of the environment. (अ) वर्तमान विकास रणनीतियाँ प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम दोहन की माँग करती हैं। परिणामस्वरूप प्रकृति का दोहन उसकी वहन क्षमता से अधिक किया जाता है। आज अपनाई गई उत्पादन तकनीकें कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर रही हैं। प्लास्टिक और अन्य अनिम्नकरणीय उत्पादों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है। (ब) अतीत में, मांग, पूर्ति से कम थी। सभ्यता के शुरुआती दिनों में, पर्यावरणीय संसाधनों और सेवाओं की मांग उनकी पूर्ति से काफी कम थी। प्रदूषण पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर था; और संसाधन निष्कर्षण की दर इन संसाधनों के पुनर्जनन की दर से कम थी। परिणामस्वरूप,	**2.5** **2.5** **2.5**

	पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न नहीं हुईं। वर्तमान में, मांग, पूर्ति से अधिक है। वर्तमान अवधि में, संसाधनों की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है, यानी संसाधनों की मांग उनके पुनर्जनन की दर से अधिक है। जनसंख्या विस्फोट और औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ, पर्यावरण की अवशोषण क्षमता पर दबाव काफी बढ़ गया है। इस प्रकार, आपूर्ति-मांग संबंध का प्रतिलोम पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट के लिए जिम्मेदार है।	**2.5**